क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रेस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
4-0 ब्लोक, आगाम नवकार कॉम्पलेकक्ष, नीयर सचिन रेल्वे स्टेशन,सचिन, सूरत-394230
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय
RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई. सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
4-0 ब्लोक, आगाम नवकार कॉम्पलेकक्ष, नीयर सचिन रेल्वे स्टेशन,सचिन, सूरत-394230
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 200, सोमवार, 13 अगस्त, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

दिल्ली सरकार का स्कुलों को निर्देश, मीडिया तक पहले न पहुंचे कोई अप्रिय घटना की खबर

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूलों को दुर्घटना, हिंसा, छेड़छाड़ या विरोध जैसी किसी भी अप्रिय घटना के बारे में, जानकारी मीडिया तक पहुंचने से पहले, तत्काल उसे सूचित करने का निर्देश दिया है ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके और शिक्षा विभाग को शर्मिंदगी भी नहीं उठानी पड़े। यह निर्देश शहर में एनडीएमसी के एक स्कूल परिसर में एक इलेक्ट्रीशियन द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किए जाने की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण है। शिक्षा निदेशालय ने स्कूल के प्राचार्यों को एक परिपत्र भेजा है जिसमें कहा गया है, ''किसी अप्रिय घटना की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने और उच्च प्रशासनिक स्तरों पर ऐहतियाती उपाय करते हुये सभी स्कूलों के प्रमुखों को हिंसा, दुर्घटना, धरना, लड़ाई, आग, विरोध, प्रदर्शन, चोरी, भगदड़, छेड़छाड़, गंभीर जख्म, खुदकुशी का प्रयास या मौत जैसी किसी भी अप्रिय घटना के बारे में, उस समय मौजूद वरिष्ठ शिक्षा विभाग के अधिकारी को तत्काल सूचित करने का निर्देश दिया जाता है।'' इसमें कहा गया है कि कुछ मामलों में स्कूल के प्रमुखों के बजाए मुख्यालय तक मीडिया या अन्य स्रोतों के माध्यम से ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट आती है जिसके कारण समय पर उपयुक्त कार्रवाई नहीं हो पाती और छात्रों के बचाव और सुरक्षा का खतरा बढ़ जाता है । कई बार यह विभागों के लिए भी शर्मिंदगी का कारण बनता है। इसलिए ऐसी सभी घटनाओं को बिना किसी देर के वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। आप सरकार ने कहा कि अगर स्कूल की प्राचार्य उच्च पदाधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने में सक्षम नहीं होती है तो तत्काल टेलीफोन से सूचना देना होगा और इसके बाद उसी दिन विस्तृत रिपोर्ट देना है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह राजधानी में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की के साथ कथित बलात्कार की घटना हुई थी जिससे स्कूल परिसर में छात्रों के बचाव और सुरक्षा पर बहस फिर से शुरू हो गई है। दो साल की लड़की से बलात्कार की घटना के बाद दिल्ली महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मामले का ब्यौरा मांगा था।

इमरान के शपथ समारोह में शामिल होंगे सिद्धू, शिवसेना ने कहा-पहले शहीद मेजर के घर जाओ

मुंबई। क्रिकेटर से राजनीतिज्ञ बने इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद के लिए 18 अगस्त इस्लामाबाद में प्रस्तावित उनके शपथ ग्रहण समारोह में पंजाब के कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है। सिद्धू ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से पाकिस्तान की इजाजत मांगी है। वहीं शिवसेना ने सिद्धू के पाकिस्तान जाने पर विरोध किया है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि सिद्धू को इमरान के शपथ समारोह में शामिल होने पाकिस्तान जाने से पहले सीमा पर शहीद हुए कौस्तुभ राणे के घर जाना चाहिए। राउत ने कहा कि नवजोत शहीद मेजर कौस्तुभ राणे के घर जाकर उनके परिवार से , उनके बच्चे से और उनकी पत्नी से मिलना चाहिए। अगर उन्हें तसल्ली होती है तो फिर वे पाकिस्तान जाकर इमरान से मिलने की सोचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने जा रहे पूर्व क्रिकेटर इमरान खान को गिफ्ट में बैट भेजा है। मोदी ने यह बैट हाई कमिशनर अजय बसारिया के हाथ पाकिस्तान भिजवाया है। बैट के साथ मोदी ने इमरान खान को शुभकामनाओं का संदेश भी भेजा है। इस बैट में खास बात यह है इसपर पूरी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के हस्ताक्षर हैं। उल्लखेनीय है कि सिद्धू ने आमंत्रण प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए कहा कि खान ने टेलीफोन पर व्यक्तिगत रूप से उन्हें समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने बताया कि टेलीफोन पर संक्षिप्त बातचीत में खान ने मीडिया में उनकी तारीफ करने के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। वहीं सिद्धू ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय को आमंत्रण प्राप्त होने के बारे में सूचित कर इस्लामाबाद जाने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने राज्य के सचिव (कार्मिक) कृपाशंकर सरोज को भी उनकी प्रस्तावित इस्लामाबाद यात्रा को लेकर औपचारिक कार्रवाई करने को कहा है।

उन्होंने बताया कि उनकी पूर्व क्रिकेटर कपिल देव से भी बातचीत हुई है और उन्होंने भी आमंत्रण इमरान की ओर से आमंत्रण पत्र प्राप्त होने की बात कही है।

स्वतंत्रता दिवस: मोदी करेंगे राजीव और नरसिम्हा राव की बराबरी

नेशनल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर बुधवार को जब लाल किले के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे तो वह पांच या उससे अधिक बार यह सम्मान हासिल करने वाले देश के सातवें और दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे। मई 2014 में देश की बागडोर संभालने वाले मोदी ने उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और बुधवार को वह पांचवीं तथा अपने मौजूदा कार्यकाल में अंतिम बार लालकिले पर तिरंगा फहरायेंगे। ऐसा करने वाले वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दूसरे नेता होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी छह बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा चुके हैं। अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव में यदि मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने में सफल रहते हैं तो वह इस मामले में वाजपेयी से आगे निकल सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्रियों राजीव गांधी और पी वी नरसिम्हा राव ने भी पांच-पांच बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और बुधवार को मोदी उनके बराबर आ जायेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की बात की जाये तो अब तक पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु का रिकार्ड नहीं टूट पाया है। पंडित नेहरु ने 1947 से लेकर 1963 तक लगातार 17 बार लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया।

श्रीनगर- शहीद एसओजी जवान को सुरक्षाबलों ने दी सलामी, बचकर भाग निकले आतंकी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की शीतकालीन राजधानी श्रीनगर में रविवार सुबह सेना और आतंकवादियों की मुठभेड़ में राज्य पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) का एक जवान शहीद हो गया। पुलिस महानिदेशक एस पी वेद ने बताया कि आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस के विशेष अभियान समूह, सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने मिलकर शनिवार रात श्रीनगर के बटमालू में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के अंदेशे वाले एक घर की घेराबंदी शुरू की तो वहां छिपे आतंकवादियों ने हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी गोलीबारी की और मुठभेड़ शुरू हो गई। इस गोलीबारी में पुलिस के एसओजी का एक जवान शहीद हो गया और सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आतंकवादी फायदा उठाकर वहां से भाग निकले।

वर्ल्ड रिकॉर्ड : इंदौर में फहराया गया 12 किलोमीटर लंबा तिरंगा

इंदौर । जिला में 12 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगा' फहराने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। यह ध्वज शहर के महू नाका से चाणक्यपुरी चौराहे के बीच फहराया गया। इससे पहले मथुरा में 10 किलोमीटर और गोरखपुर में 11 किलोमीटर लंबा तिरंगा फहराकर विश्व कीर्तिमान बनाया जा चुका है। इस तिरंगे को दो पंक्तियों में 6 किलोमीटर लंबाई में सैकड़ों युवाओं ने थाम रखा था। कार्यक्रम में हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने शिरकत की। इसमें समाज के 40 से ज्यादा वर्गों के लोगों ने पारम्परिक वेशभूषा में कदमताल की, तो वहीं सुरक्षा बलों ने मार्चपास्ट किया। इससे पहले इंदौर में ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आजादी महोत्सव के तहत रविवार सुबह इंदौर के देवी अहिल्या एयरपोर्ट से मिनी मैराथन का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में शहर के युवाओं बच्चों और समाज के लोगों ने भाग लिया। 'स्वच्छतम, स्वस्थतम, सभ्यतम' के नारे के साथ एयरपोर्ट से सात किलोमीटर की मिनी मैराथन को इंडियन क्रिकेट टीम चयन समिति के पूर्व सचिव संजय जगदाले ने हरी झंडी दिखाकर

रवाना किया। इस मैराथन में बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक, खिलाड़ी, स्कूली बच्चे और एयरपोर्ट के कर्मचारी शामिल हुए। देवी अहिल्या एयरपोर्ट इंदौर की डायरेक्टर आर्यमा सन्याल ने बताया कि भारत पर्यटन विकास विभाग के सहयोग से इस मिनी मैराथन आयोजन किया गया था। उन्होंने बताया कि इंदौर स्वच्छता में दो बार नंबर वन रहा है अब हम इंदौर को स्वस्थतम और सभ्यतम बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं. इसी के तहत आज इस मिनी मैराथन का आयोजन किया गया था.

बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही, केरल दौरे पर पहुंचे राजनाथ सिंह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह बाढ़ प्रभावित केरल का हवाई सर्वेक्षण लेने के लिए राज्य में पहुंच गए हैं। गृह मंत्री के साथ पर्यटन मंत्री के जे. अल्फोंस और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। वे बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। वहीं राजनाथ राज्य के मुख्यमंत्री पी.विजयन और राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ केरल तथा केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए तलाशी, बचाव एवं राहत उपायों की समीक्षा करेंगे। केरल में बारिश और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचा रखी है। यहां पर बारिश के कहर से तीन दिनों में अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। इस आपदा के समय एनडीआरएफ की टीमें राज्य में डटी हुई हैं और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है।

सेना के जवानों ने अब तक 398 लोगों और 12 मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है।

घुसपैठ की समस्या को सुलझाना नहीं चाहती मोदी सरकार: तरुण गोगोई

नेशनल डेस्क। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरूण गोगोई ने दावा किया कि एनआरसी को अद्यतन करने की पहल उन्होंने ही थी लेकिन भाजपा इसके ठीक तरह से संभालने में विफल रही जिसके कारण एक दोषपूर्ण मसौदा प्रकाशित किया गया जिसमें 40 लाख से अधिक लोगों का नाम छूट गया। असम के तीन बार मुख्यमंत्री रहने वाले गोगोई ने आरोप लगाया कि घुसपैठ की समस्या हल करने में भाजपा की दिलचस्पी नहीं है बल्कि अगले लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों में एक चुनावी एजेंडा के रूप में इसका इस्तेमाल करने का है। तरूण गोगोई ने एक साक्षात्कार में बताया कि भाजपा ने विदेशियों के मुद्दे पर हमेशा सांप्रदायिक आधार पर राजनीति की है और समस्या सुलझाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले हमेशा घुसपैठ का मुद्दा उठाया जाता है और एक बार फिर यह अगले चुनाव में उठाया जाएगा। भाजपा इसे सुलझाना नहीं चाहती है क्योंकि यह उनके द्वारा प्रस्तुत नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 से स्पष्ट है जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक विदेशियों को इसमें लाने का है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विदेशियों को बाहर नहीं करना चाहते हैं बल्कि वह और लोगों को लाने में दिलचस्पी रखते हैं। भाजपा इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है और यही उसका गठबंधन सहयोगी असम गण परिषद (अगप) भी चाहता है।

मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी नागरिक को भारत देश नहीं छोड़ना पड़ेगा।

मॉब लिंचिंग पर बोले प्रधानमंत्री मोदी- वजह कोई भी हो, यह एक जघन्य अपराध

नेशनल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एएनआई को दिए इंटरव्यू में कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यह विपक्ष का महागठबंधन नहीं बल्कि विरासत का महागठबंधन है। वहीं मॉब लिंचिंग पर पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी एक भी घटना का देश में होना दुखद है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे वजह कोई भी हो लेकिन यह एक जघन्य अपराध है। मोदी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी हालात में, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता और हिंसा नहीं कर सकता। पीएम ने संसद में राहुल गांधी के गले मिलने से जुड़े सवाल पर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष इशारा देखकर खुद तय करें कि उनकी हरकत कैसी थी। उन्होंने कहा कि अब देखना यह है कि यह महागठबंधन चुनाव के पहले टूटता है या फिर चुनाव के बाद। पीएम मोदी ने एनडीए के सहयोगी दलों के नाखुश होने की खबरों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए के सहयोगी दल एकजुट हैं। अविश्वास प्रस्ताव और राज्यसभा उपसभापति चुनाव में जीत इसका सबूत हैं। उन्होंने कहा कि हमको एनडीए से बाहर के दलों का भी समर्थन मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि जीएसटी पर भी लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने उनको नकार दिया है। हक्रष्ट पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों का खुद के ऊपर से विश्वास खत्म हो गया है, उन लोगों को जन समर्थन खोने का डर सता रहा है। ऐसे लोग गृहयुद्ध, खूनखराबा और देश के टुकड़े-टुकड़े जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भरोसा खोने वालों को अब देश की संस्थाओं पर भी भरोसा नहीं नहीं हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि गृहयुद्ध और खूनखराबा की बात करने वालों को देश के नब्ज की समझ नहीं है। पीएम मोदी ने एएनआई को दिए खास इंटरव्यू में कहा कि मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी नागरिक को भारत देश नहीं छोड़ना पड़ेगा। एक प्रक्रिया के तहत ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा। पीएम मोदी ने इंटरव्यू के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध और लिंचिंग की घटनाओं को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि समाज में शांति और एकता के सुनिश्चित करने के लिए हर किसी को राजनीति से उठकर आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं और मेरी पार्टी ऐसी घटनाओं का कड़ा विरोध करते हैं। आरक्षण के मुद्दे पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसको लेकर कोई दूसरा विचार नहीं है। आरक्षण जारी रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी से तुलना करते हुए कहा, मैं कामदार हूं और नामदार से खुद की तुलना नहीं कर सकता हूं।

संक्षिप्त समाचार

अब देश में सी-प्लेन उड़ाने का सपना होगा पूरा, मोदी सरकार ने दी हरी झंडी

नेशनल डेस्क। अब देश में भी सी प्लेन चलाने का सपना पूरा होने जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में सी-प्लेन उतारने के लिए अड्डे बनाने की मंजूरी दे दी है। इसके पहले चरण के लिए ओडिशा के चिल्का झील और गुजरात के सरदार सरोवर बांध तथा साबरमती रिवर फ्रंट की पहचान की गयी है। एक अधिकारी ने आज इसकी जानकारी दी। इस प्रस्ताव को नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने मंजूरी दी। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इस संबंध में इस साल जून में नियमन जारी किया था जिसमें जलाशयों में बने एयरोड्रम के लाइसेंस की जरूरतों एवं प्रक्रियाओं का जिक्र किया गया था। अधिकारी ने कहा कि चूंकि किसी भी विमानन कंपनी से इस क्षेत्र में बाजार व मांग संबंधी ऐतिहासिक आंकड़े नहीं मिले हैं, परियोजना पर प्रायोगिक तौर पर काम किया जाएगा। इससे हवाई संपर्क को विस्तृत करने के लिए एम्फीबियन विमानों (जल एवं स्थल दोनों से उड़ान भरने में सक्षम) के परिचालन का रास्ता तैयार होगा। प्रस्ताव के तहत पर्यटन तथा धार्मिक महत्व के स्थानों के नजदीक ऐसे एयरोड्रम बनाये जाएंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने इसके लिए ओडिशा, गुजरात, असम, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में जगहों की पहचान पहले ही कर ली है। अधिकारी ने कहा कि पहले चरण में जलाशयों में एयरोड्रम बनाने के लिए ओडिशा में चिल्का झील तथा गुजरात में सरदार सरोवर बांध और साबरमती रिवर फ्रंट की पहचान की गयी है। इससे पहले नागर विमानन सचिव आर.एन.चौबे ने भी कहा था कि उनका मंत्रालय उड़ान योजना के तीसरे चरण के तहत सीप्लेन का परिचालन शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। डीजीसीए के अनुसार, जलाशय में बने एयरोड्रम के लिए आवेदन करने वाले किसी भी निकाय को रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और नौवहन मंत्रालय समेत विभिन्न प्राधिकरणों की मंजूरी लेनी होगी। यह लाइसेंस दो साल के लिए वैध होगा।

आदिवासी कारीगारों के बनाए बांस के पंखे बढ़ाएंगे 15 अगस्त की शोभा, रक्षा मंत्री ने खरीदें

नई दिल्ली। आदिवासी कारीगरों द्वारा बनाया गया और पेंट किया हुआ बांस का पंखा इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मौजूद अतिविशिष्ट लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र होगा क्योंकि समारोह में शिरकत करने वाले सांसदों, मंत्रियों और अन्य गणमान्य अतिथियों को दिए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने बांस के बनाए गए ऐसे हजारों पंखे खरीदे हैं। आदिवासी उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के सरकार के मकसद से ऐसा कदम उठाया गया है। केंद्रीय अदिवासी मामलों के मंत्रालय के अधीन आने वाले आदिवासी सहकारिता विपणन विकास परिसंघ (टीआरआईएफईडी) ने बांस के ये पंखों की खेप रक्षा मंत्रालय को अपूर्ति कराई है। रक्षा मंत्रालय ही स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन करता है। बांस के बने इन पंखों की पेशकश समारोह में मौजूद मंत्रियों, सांसदो और अन्य अतिविशिष्ट लोगों को किएं जाएंगे। टीआरआईएफईडी के प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्ण ने बताया, ''पश्चिम बंगाल के महली आदवासी समुदाय के कलाकारों ने बांस के इन पंखों को बनाया है। इन पंखों पर दोनो तरफ आदिवासी चित्रांकन किया गया है। एक पंखे की कीमत 150 रूपये है और ये पैसे आदिवासी लोगों को मिलेगा।'' ये पंखे बिक्री के लिए ट्राइब्स इंडिया डाट काम और अमेजन पर उलब्ध है। मध्य प्रदेश के सहारिया आदिवासी समुदाय के लोगों ने रोपे जा सकने वाली राखियों का निर्माण किया है। इसके लिए गैर रसायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। इस रोपी जाने वाली राखी के किट में एक पेंसिल (ल्युपिन के फूल), एक पत्र (टमाटर) और 'रोली एवं चावल' के लिए कागज के बाक्स होंगे। इसकी कीमत 120 रुपए है जो ट्राइब्स इंडिया की 42 दूकानों, ट्राइब्स इंडिया डाट काम, अमेजन, स्नैपडील, पेटीएम और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। रक्षा बंधन के लिए परंपरागत कपड़े भी ट्राइब्स इंडिया की दूकानों तथा ई कामर्स वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सर्वे: भारत में 89प्रतिशत लोग हैं तनाव के शिकार

नई दिल्ली। ''इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यूं है।'' शहरयार ने करीब 40 बरस पहले महानगरीय जीवन की भागदौड़ पर यह सवाल पूछा था, लेकिन आज आलम यह है कि बात शहर से बढ़कर देश तक पहुंच गई है। एक हालिया सर्वे की मानें तो भारत में 89 प्रतिशत लोग तनाव का शिकार हैं, जबकि वैश्विक औसत 86 प्रतिशत है। सर्वे में शामिल लोगों में से हर आठ तनावग्रस्त लोगों में से एक व्यक्ति को इन परेशानियों से निकलने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग कई कारणों से अपनी इस समस्या का इलाज नहीं करा पाते। इनमें सबसे बड़ी समस्या इसके इलाज पर आने वाले खर्च की है। यह सर्वे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, चीन, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित 23 देशों में किया गया और इसके नतीजे भारत के लिए चिंता की बात हो सकते हैं क्योंकि दुनिया के इन तमाम देशों के मुकाबले भारत के लोग कहीं ज्यादा तनाव का सामना कर रहे हैं। सिग्ना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस ने अपने सिग्ना '360 डिग्री वेल-बीइंग सर्वेक्षण-फ्यूचर एश्योर्ड' की एक रिपोर्ट जारी की है। विकसित और कई उभरते देशों की तुलना में भारत में तनाव का स्तर बड़े रूप में है। इस सर्वे के दौरान दुनिया के विभिन्न देशों में रहने वाले 14,467 लोगों का ऑनलाइन इंटरव्यू लिया गया। जिसके बाद ये सामने आया कि भारत लगातार चौथे साल तनाव के मामले में दुनिया के बाकी देशों से कहीं आगे है। भारत में जितने लोगों को इस सर्वे में शामिल किया गया उनमें से 75 प्रतिशत का कहना था कि वह अपने तनाव की समस्या के बारे में चिकित्सकीय मदद नहीं ले पाते क्योंकि अगर वह इस समस्या के निदान के लिए किसी पेशेवर चिकित्सक के पास जाते हैं तो उन्हें इसके लिए बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। तनाव के कारणों की बात की जाए तो लोगों का काम और उनकी आर्थिक स्थिति इसकी सबसे बड़ी वजह है। हालांकि ज्यादातर लोगों का कहना था कि अगर उनके कार्यस्थल का माहौल उनके अनुकूल हो तो उनके तनाव का स्तर कम हो सकता है। वैसे यह राहत की बात है कि सर्वे में शामिल 50 प्रतिशत लोगों ने कहा कि इस बारे में बात करने पर उन्हें कार्यस्थल पर सहयोग मिला और वह कार्यस्थल स्वास्थ्य कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं।

सच्चे लोगों को कभी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती और असली फूलों को कभी इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है ।

आरक्षण को लेकर चर्चाएं गरम

यह सकारात्मक भेदभाव की अवधारणा से निकली है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में पिछड़ों और दलित जातियों को समान सामाजिक हैसियत दिलाने और उनके प्रति भेदभाव दूर करने का औजार माना जाता है। आजकल आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर चर्चाएं गरम हैं। सरकार भी आरक्षण को लेकर नई उठती मांगों को शांत करने के लिए शायद कुछ ऐसी ही पेशबंदी करती नजर आ रही है। यह बहस कुछ ऐसे आक्रामक ढंग से उठाई जा रही है कि आरक्षण की व्यवस्था के कुछ समर्थकों की भी दलीलें कमजोर पड़ती दिख रही हैं या वे कुछ रक्षात्मक मुद्रा में नजर आने लगे हैं। लेकिन कई स्वाभाविक सवाल भी खड़े होते हैं। मसलन, आर्थिक आधार पर आरक्षण से कितनी बड़ी आबादी को राहत दी जा सकेगी ?

सतीश पेडणोकर

आरक्षण की वह प्रतिश्रुति तो अभी भी अधूरी है, जिसके जरिए संविधान में सदियों से उत्पीड़ित और वंचित समुदायों को सत्ता-तंत्र में हिस्सेदारी देकर सामाजिक ताने-बाने में बदलाव की उम्मीद की गई थी। उसका मूल लक्ष्य तो जाति की जकड़बंदी और ऊंच-नीच की व्यवस्था को तोड़ना था। असल में आरक्षण गरीबी या आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं है। यह सकारात्मक भेदभाव की अवधारणा से निकली है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में पिछड़ों और दलित जातियों को समान सामाजिक हैसियत दिलाने और उनके प्रति भेदभाव दूर करने का औजार माना जाता है। आजकल आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर चर्चाएं गरम हैं। सरकार भी आरक्षण को लेकर नई उठती मांगों को शांत करने के लिए शायद कुछ ऐसी ही पेशबंदी करती नजर आ रही है। यह बहस कुछ ऐसे आक्रामक ढंग से उठाई जा रही है कि आरक्षण की व्यवस्था के कुछ समर्थकों की भी दलीलें कमजोर पड़ती दिख रही हैं या वे कुछ रक्षात्मक मुद्रा में नजर आने लगे हैं। लेकिन कई स्वाभाविक सवाल भी खड़े होते हैं। मसलन, आर्थिक आधार पर आरक्षण से कितनी बड़ी आबादी को राहत दी जा सकेगी ? आर्थिक पिछड़ेपन को अगर अवसरों की कमी के आधार पर परिभाषित किया जाए तो सरकारी क्षेत्र की नौकरियों के लगातार सिकुड़ते जाने और निजी क्षेत्र में अवसरों के उस पैमाने पर इजाफे न होने के कारण महज आर्थिक आरक्षण से कोई बड़ा लक्ष्य तो नहीं हासिल किया जा सकता। जाहिर है, आरक्षण रोजगार के संकट का कोई इलाज नहीं है। तो, फिर इसके क्या मायने हैं ?इसमें दो राय नहीं कि आर्थिक स्थितियां कुछ ऐसी बदली हैं कि हमारी आबादी का ज्यादातर हिस्सा अवसरों से वंचित महसूस करने लगा है। खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लगातार टूटते जाने से उन जातियों और समुदायों में भी बेचैनी बढ़ रही है, जो अपने-अपने क्षेत्रों में खास दबदबा रखती थीं। शायद एक बड़ी वजह यह भी है कि अरसे से आरक्षण की दरकार महसूस न करने वाली जातियां भी अब इसकी मांग करने लगी हैं और आंदोलनरत हैं। ये जातियां अपने-अपने इलाकों में रसूख रखती हैं, इसलिए खासकर मुख्यधारा की बड़ी पार्टियां उनकी अनदेखी करने का जोखिम नहीं उठा सकतीं। यही वजह है कि आरक्षण को सामाजिक न्याय का औजार मानने वाली पार्टियों और लोगों में भी एक तरह की दुविधा देखी जा सकती है। इसी दुविधा का एक नतीजा यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की दलीलों से एक हद तक सहमत होती दिख रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि आरक्षण का वह उद्देश्य आजादी के सात दशकों में क्या पूरा हो चुका है या होने के करीब है, जो सामाजिक न्याय के नजरिए से सोचा गया था। यह देखना इसलिए जरूरी है कि घटते अवसरों के दौर में इसका दंश बेशक समाज के निचले पायदान पर ? स्थित लोगों को सबसे ज्यादा महसूस हो रहा होगा। इसका एक रूप तो किसानों और खेतिहर मजदूरों की लगातार आत्महत्या की घटनाओं में भी दिख रहा है। पिछले कुछ साल में खेतिहर मजदूरों के आत्महत्या करने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जो पहले कम सुनने को मिलती थीं।इसमें दो राय नहीं कि घटते अवसरों का रिश्ता पिछली सदी में नब्बे के दशक से ज्यादा है, जब आर्थिक उदारीकरण के बाद कृषि और छोटे तथा स्थानीय उद्योग-धंधों के बदले बड़ी पूंजी के बड़े उद्योगों और निजीकरण को प्रश्रय का दौर तेज हुआ। नतीजतन शहरी सेवा क्षेत्र में तो कुछ अवसर पैदा हुए, जिन पर मध्यवर्गीय और पहले से अच्छी हालत वाले समुदायों को तो लाभ पहुंचा, लेकिन बड़ी आबादी के लिए अवसर सिकुड़ते गए। कृषि और उससे जुड़े छोटे उद्योग-धंधों के क्षेत्र में भी बड़ी कंपनियों के प्रवेश से ढेरों लोगों के आगे रोजगार का संकट खड़ा हो गया। मसलन, हर मोहल्ले-इलाके में आटा चक्कियों और स्थानीय कोल्हू लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराते होंगे। लेकिन इन क्षेत्रों में बड़ी कंपनियों के उतर आने से एक तो उसका कुछ खास क्षेत्रों में केंद्रीकरण हुआ। दूसरे, ऑटोमेशन पर जोर बढ़ने से कम लोगों की दरकार होने लगी। आप याद करेंगे तो पाएंगे कि पहले जितने धंधे स्थानीय स्तर पर चला करते थे, आज कहीं दिखते नहीं हैं। इससे यह बड़े पैमाने पर हुआ है कि जो लोग खास तरह के हुनर से अपना जीवनयापन करते थे, वे अब बेहुनर हो गए हैं। यह कितने बड़े पैमाने पर हुआ है, इस पर अभी तक कोई खास अध्ययन नहीं हुआ है। लेकिन कुछ साल पहले आए सामाजिक-आर्थिक जनगणना से एक अंदाजा मिलता है। उसके आंकड़े बताते हैं कि पांच हजार रुपये महीना आमदनी वाले परिवारों की संख्या एक-चौथाई भी नहीं है और यह भी तब है जब उस परिवार का कोई कृषि से इतर क्षेत्र में नौकरी पर है। 2014 में एनडीए सरकार आई तो मनरेगा के प्रति उसने भारी उपेक्षा दिखाई और प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहकर उसकी खिल्ली तक उड़ाई थी कि हम इसे इसलिए जारी रखेंगे क्योंकि यह कांग्रेस के सत्तर साल के कुशासन का जीता-जागता सबूत है। लेकिन 2017 और 2018 के बजटों में इस मद में बजटीय प्रावधान काफी बढ़ाना पड़ा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आधी-अधूरी, और कई बार महीनों तक न मिलने वाली, पगार के लिए भी लोग मजबूर होते जा रहे हैं। यानी रोजगार और अवसरों का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए इन संकटों का रिश्ता विकास की उस धारा से ज्यादा है, जो उदारीकरण के बाद शुरू हुई है। उदारीकरण के साथ ही नब्बे के दशक में दो और बड़ी घटनाएं हुई, जिनका हमारी सामाजिक ताने-बाने पर खासा असर हुआ। एक ओर मंडल आयोग की रपट लागू हुई और उसके साथ ही दलित अस्मिता की भावना भी जोर पकड़ी। लिहाजा, बसपा जैसी पार्टियों का उदय हुआ। दूसरी ओर उसी दौर में आरक्षण विरोधी सक्रियताएं बढ़ीं और कुछ खास वगरे से यह दलील भी उभरी कि योग्यता को तरजीह दिया जाना चाहिए, न कि आरक्षण को। बेशक वही दौर था जब राम जन्मभूमि आंदोलन भी उभरा। मंडल और दलित अस्मिता के उभार से राजनैतिक मानचित्र में पिछड़े और दलित नेताओं का दबदबा बढ़ा। सामाजिक न्याय के लिहाज से यह अहम मुकाम था, लेकिन खासकर उत्तर भारत में पिछड़े और दलित नेताओं ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बदले अपने और अपने परिवार की प्रगति में मशगूल होना बेहतर समझा। और लगभग सभी ने उदारीकरण से प्रशस्त धारा को सहर्ष स्वीकार कर लिया, जबकि वे देख रहे थे कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग तेजी से बेहुनर होते जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की दलील को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन आरक्षण की वह प्रतिश्रुति तो अभी भी अधूरी है, जिसके जरिए संविधान में सदियों से उत्पीड़ित और वंचित समुदायों को सत्ता-तंत्र में हिस्सेदारी देकर सामाजिक ताने-बाने में बदलाव की उम्मीद की गई थी। उसका मूल लक्ष्य तो जाति की जकड़बंदी और ऊंच-नीच की व्यवस्था को तोड़ना था। असल में आरक्षण गरीबी या आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं है। यह सकारात्मक भेदभाव की अवधारणा से निकली है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में पिछड़ों और दलित जातियों को समान सामाजिक हैसियत दिलाने और उनके प्रति भेदभाव दूर करने का औजार माना जाता है। आर्थिक आधार पर वर्गीकरण करने वाले मार्क्सवाद में इसीलिए यह अवधारणा नहीं है। इसी वजह से हमारी कम्युनिस्ट पार्टियां पहले इस पर जोर नहीं दिया करती थीं। कई लोग इसे ही वामपंथी पार्टियों के सिकुड़ते जाने की बड़ी वजह मानते हैं। इसके विपरीत, समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया ने आरक्षण को जाति तोड़ो की अवधारणा के साथ पेश किया। उस समय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नारा हुआ करता था, ''संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावें सौ में साठ।' गांधी और अम्बेडकर ने भी इसे जाति तोड़ो के लक्ष्य को साधने के लिए ही आगे बढ़ाया था। वैसे इन सभी विचारधाराओं के लोगों में गहरा भटकाव दिखा है। जहां तक भाजपा और संघ परिवार की बात है तो वह सोशल इंजिनियरिंग में यकीन करती रही है, सामाजिक न्याय उनके यहां उतनी बड़ी प्रतिश्रुति नहीं है। लेकिन यह तो आरक्षण की मूल अवधारणा से ही दूर हो जाने जैसा होगा। लोगों को अवसर और शिक्षा मुहैया करानी है तो उसकी व्यवस्था अलग होगी, आरक्षण तो कतई नहीं। इसलिए इस छलावे को लोगों को समझ लेना चाहिए। संभव है, यह इसलिए भी आगे बढ़ाया जा रहा हो कि मौजूदा कारपोरेटीकरण की धारा अपनी कमियों से ध्यान भटकाने के लिए इस पर जोर दे रही हो।

''आलोचना की जगह'

ये ऐसे दिन हैं, जब एक फिल्मी गाना नये मानी पाकर ''आलोचना की जगह' बना सकता है। कारण यह है : यही दौर है जब ''टायलेट', ''परमाणु' और ''सुई धागा' जैसी ''संदेशात्मक' फिल्में बनी हैं। इनमें वह आलोचनात्मक जगह छूटी रह गई है, जो ''आम आदमी की जगह' कहलाती है सुधीश पचौरी अनिल कपूर की नई रिलीज हुई ''फन्ने खां' एकदम दयनीय फिल्म है। आमिर खान की पिछली फ्लाप फिल्म ''सीक्रेट सुपर स्टार' से भी गई बीती। हर फिल्म की तरह यह भी एक ''आकांक्षा-चालित' फिल्म है। इसका नायक अनिल कपूर एक फैक्ट्री वर्कर है। फैक्ट्री बंद हो जाती तो वह मुंबई में टैक्सी चलाने लगता है। उसका एक ही ख्वाब है कि अपनी बेटी को बड़ी गायिका बनाए। इस आकांक्षा का एक कारण यह भी है कि वह भी कभी गायक बनना चाहता था, लेकिन अपनी परिस्थितियों के कारण न बन पाया। इसलिए भी अपनी बेटी को गायिका बनाना चाहता है।यहीं कहीं यह फिल्म एक गाने के जरिए अपने को समकालीनता से जोड़ बैठती है: गीत पूछता है : मेरे अच्छे दिन कब आएंगे ? यों, गाने की धुन कोई कमाल वाली नहीं है। न ही गाने में कुछ कलात्मकता है, लेकिन दिनों का फेर देखिए कि आज की स्थिति पर यह गाना तीखा ''पॉलिटीकल कमेंट' बन गया। ''यू ट्यूब' पर बहुत से लोगों ने इसे लाइक किया। ढेर सारे लोगों ने ऐसे ''कमेंट' लिखे, जिन्हें देखकर कहा जा सकता है कि 2019 के चुनाव में यह गाना विपक्ष का ''थीम सांग' बन सकता है क्योंकि यह पूछता है : मेरे अच्छे दिन कब आएंगे ? गीतकार इरशाद कामिल ने आज की स्थिति को बखूबी पकड़ा है। गाने के शुरू के बोल कुछ इस प्रकार हैं : ''खुदा तुम्हें प्रनाम है सादर/पर तूने दी बस एक ही चादर/क्या ओढ़े क्या बिछाएंगे/मेरे अच्छे दिन कब आएंगे ?/दो रोटी और एक लंगोटी/एक लंगोटी और वो भी छोटी/इसमें क्या बदन छिपाएंगे/मेरे अच्छे दिन कब आएंगे ?'। ''अच्छे दिन' पर यह शायद पहली बड़ी काव्यात्मक ''शिकायत' है, जिसे सोशल मीडिया के टिप्पणीकारों ने हाथों-हाथ लिया। कहते हैं कि सोशल मीडिया के हल्ले और रिलीज के आठ दिन बाद फिल्म वालों ने इसे पॉजिटिव बना दिया। नायक जो चाहता था, वह फिल्म के अंत तक पूरा हो जाता है। उसकी बेटी बड़ी गायिका बन जाती है, तब पिता इस बदले हुए बोल वाले टुकड़े को गाता है : ''जो चाहा था वो हो भी गया है..मेरे अच्छे दिन अब आए रे!'हमें नहीं मालूम कि गाने को लेकर इस विवाद को फिल्म वालों ने प्रायोजित किया कि या वह सोशल मीडिया पर अपने आप बना। लेकिन इससे इतना साफ हो गया कि ये ऐसे दिन हैं, जब एक फिल्मी गाना नये मानी पाकर ''आलोचना की जगह' बना सकता है। इसका कारण यह है : यही दौर है जब बॉलीवुड में ''टायलेट', ''परमाणु' और ''सुई धागा' जैसी कुछ ''संदेशात्मक' फिल्में बनी हैं। इनमें वह आलोचनात्मक जगह छूटी रह गई है, जो ''आम आदमी की जगह' कहलाती है। फन्ने खां के इस गाने ने संयोगवश उस असंतोष और उन अपूर्ण आकांक्षाओं को व्यक्त कर लोगों को एक आलोचनात्मक जगह मुहैया कर दी है। इसीलिए यह गाना हिट हुआ है। बाद में इस गाने के बोलों को पॉजिटिव बनाया गया तो पहले संस्करण के बोलों की आलोचनात्मकता को छिपाने के लिए। राजनीति पर कटाक्ष करने वाली फिल्मों की एक लंबी लिस्ट है। अंग्रेजों के जमाने में बनी दिलीप कुमार वाली ''शहीद' पर आजादी के आंदोलन की छायाएं साफनजर आती हैं। आजादी मिलने के बाद वी शांताराम की ''दो आखें बारह हाथ', ''नवरंग' और ''नया दौर' पर गांधी-नेहरू के विचारों की छाप साफनजर आती है जबकि ''दो बीघा जमीन' पर प्रगतिशील आंदोलन का सीधा असर। ऐसी अनेक फिल्में गिनाई जा सकती हैं। ऐसी फिल्में यही सिद्ध करती हैं कि चाहे कितनी ही फॉमरूलाबद्ध क्यों हों, पॉपूलर फिल्में अपने समाज के यथार्थ के किसी न किसी पहलू पर कमेंटरी करती ही हैं।

समकालीनता और रससिंचित आलोचनात्मकता ही उनको पॉपूलर बनाती है। कभी-कभी उनको लेकर सत्ता की भंवें भी टेढ़ी हुई हैं। जैसे ''किस्सा कुरसी का' फिल्म को आपातकाल के आसपास 'बैन' कर दिया गया था। इससे कुछ ही कम ताड़ना ''आंधी' को झेलनी पड़ी थी। अगर राजनीति से दो-चार करती फिल्मों की लिस्ट बनाई जाए तो यह स्थान छोटा ही पड़ेगा!

''फन्ने खां' के उक्त गाने ने अगर लोगों का ध्यान खींचा और वह जुबान पर चढ़ गया और सोशल मीडिया में जाकर आलोचनात्मकता पैदा करने लगा तो इसका कारण यही है कि समकालीन राजनीति और अर्थनीति पर वह अचानक एक टिप्पणी बन गया। इसी पहलू को लोगों ने पकड़ लिया। यह विवाद बताता है कि सोशल मीडिया की वजह से हमारी जनता अपनी आकांक्षाओं के प्रति अब अधिक संवेदनशील हो चली है, और कोई भी बात, कोई एक वाक्य, कोई फिल्म, उसके किसी गीत का एक टुकड़ा कोई एक चुटकुला, एक किस्सा, बात की बात में, आलोचना की जरूरी जगह पैदा कर सकता है।

सत्संग

जीवन में सफलता

केवल लंबी छलांग से जीवन में सफलता नहीं मिलती। उसके लिए एक उड़ान भी जरूरी है। उड़ान का मतलब परिंदों से अच्छा और कौन समझ सकता है। लेकिन बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले परिंदे भी यह नहीं जान पाते हैं कि उड़ान के लिए दो पंखों की जरूरत होती है। पक्षी तो केवल उड़ना जानते हैं। उनके लिए वह जीवन की एक ऐसी क्रिया है, जो पुरखे उन्हें सिखा गए। लेकिन, मनुष्य उड़ान को ठीक से समझ सकता है। उड़ान का मतलब समझ लें तो यह पता चल जाएगा कि पक्षी भले ही दो पंख से उड़ लें पर मनुष्य को उड़ने के लिए तीन पंख लगेंगे और ये हैं- ज्ञान, कर्म और उपासना के। जब उड़ान ले रहे होते हैं तो सबसे बड़ी बाधा हमारे दुर्गुण ही बनते हैं। इन्हीं दुर्गुणों से निपटने के लिए पंख गति के भी काम आते हैं और हथियार बनकर सुरक्षा के भी। जटायु ने अपने पंखों को शस्त्र बनाते हुए ही रावण से टक्कर ली थी। जीवन की कुछ यात्राएं ऐसी हैं जहां कि सी एक पंख के सहारे नहीं जाया जा सकता। हमारे पास ज्ञान, कर्म और उपासना रूपी पंख हैं और ज़िंदगी की उड़ान में इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। जो केवल ज्ञान मार्ग से चलेंगे वे बाकी दो चीजें यानी कर्म और उपासना का मतलब नहीं समझ पाएंगे और उनका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। न तो केवल कर्म से और न केवल उपासना से जीवन की यात्रा पूरी हो सकती है। ज्ञान,कर्म और उपासना के तीनों पंखों से भरी उड़ान उस ऊंचाई पर पहुंचा देगी, जिसे आप छूना चाहते हैं।

चलते चलते

कश्मीर संबंधी अनुच्छे द 35-ए पर सुनवाई में हर्ज क्या है?

अनुच्छेद 35-ए के तहत यह प्रावधान है कि जम्मू-कश्मीर में बाहर के लोग जमीन और घर जैसी अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। इसे 'वी द सिटीजन' एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अलगाववादियों को तो मौका मिल गया। वे कश्मीर हितैषी होने का दिखावा करते हुए इसके विरोध में बंद और हिंसा में लग गए हैं। कुछ वर्षों से कश्मीर की जनता ने अलगाववादियों को सहयोग देना कम कर दिया है, इसलिए इस मुद्दे को वे भुनाना चाहते हैं। अभी तो सिर्फ सुनवाई शुरू हुई है और इन्होंने भय का माहौल बनाना शुरू कर दिया हैं। अलगाववादियों के बच्चे तो विदेशों में उच्च शिक्षा ले रहे हैं और यहां वे स्कूल बंद करवा रहे हैं। इनके परिवार तो विदेशों में आधुनिक जीवन जी रहे हैं और ये कश्मीर में धार्मिक कट्टरता और रुढ़ि वादिता फैला रहे हैं। अलगाववादी चाहते हैं की कश्मीरी जनता अलग-थलग पड़ी रहे। यदि बाहरी लोग यहां आकर बस जाएंगे तो कश्मीर की जनता को बरगला ना और राष्ट्र विरोधी काम करवाना बहुत कठिन हो जाएगा। बाहरी राज्यों के लोगों के बसने से न केवल अलगाववादियों का प्रभाव कमजोर होगा बल्कि बाहरी लोगों के संपर्क में आने से कश्मीरी जनता भी जागरूक होगी। बाहरी राज्यों के लोगों के संपर्क में आने से रूढ़िवादिता और धार्मिक कट्टरता में भी कमी आएगी और धर्म के नाम पर हिंसा और जेहाद जैसी घटनाएं भी बंद हो जाएंगी। कश्मी र और कश्मी रियों के विकास के रास्ते खुलेंगे। वैसे कश्मीरी जनता समझ चुकी हैं कि पाकिस्ता न परस्त इन अलगाववादियों की फंडिंग आईएसआई करती रही है। कश्मीरी धीरे-धीरे बाकी दुनिया से जुड़ने के बाद ये जानने लगे हैं कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके बच्चों को पत्थरों की नहीं शिक्षा की जरूरत है। अचरज यह है कि वोट बैंक के चक्कर में बहुत सारे राजनीति क दल भी चाहते हैं कि इस मुद्दे पर सुनवाई न हो। याचिका पर फैसला करना सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है, इसे लेकर अशांति फैलाना सरासर गलत है। आज नहीं तो कल कश्मीरी भी देश और समाज की मुख्यधारा से जुड़ जाएंगे और अलगाववादियों के खतरनाक मंसूबों में नाकाम हो जाएंगे।

> कुछ वर्षों से कश्मीर की जनता ने अलगाववादियों को सहयोग देना कम कर दिया है, इसलिए इस मुद्दे को वे भुनाना चाहते हैं। अभी तो सिर्फ सुनवाई शुरू हुई है और इन्होंने भय का माहौल बनाना शुरू कर दिया हैं। अलगाववादियों के बच्चे तो विदेशों में उच्च शिक्षा ले रहे हैं और यहां वे स्कूल बंद करवा रहे हैं। इनके परिवार तो विदेशों में आधुनिक जीवन जी रहे हैं।

फोटोग्राफी...

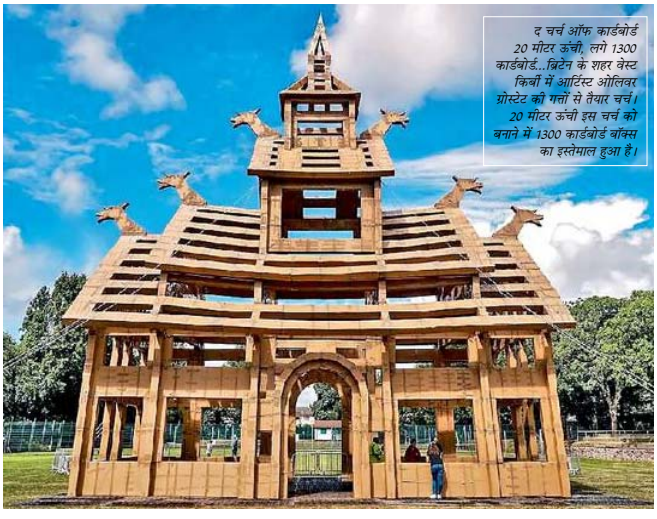

द चर्च ऑफ कार्डबोर्ड 20 मीटर ऊंची, लगे 1300 कार्डबोर्ड...ब्रिटेन के शहर वेस्ट किर्बी में आर्टिस्ट ओलिवर ग्रोस्टेट की गत्तों से तैयार चर्च। 20 मीटर ऊंची इस चर्च को बनाने में 1300 कार्डबोर्ड बॉक्स का इस्तेमाल हुआ है।

''नस्ली हिंसा'

पिछले एक पखवाड़े के दौरान इंग्लैंड और अमेरिका में घृणा- अपराध से जुड़ीं दो ऐसी घटनाएं हुई जो हर भारतीय के लिए चुभने वाली थीं, और इससे कोई भी भारतीय अपने को अपमानित महसूस करेगा। भारत सरकार के एक वरिष्ठ नौकरशाह और उसके परिवार को ब्रिटिश एयरवेज के क्रू सदस्यों ने महज इसलिए विमान से उतार दिया कि सीट बेल्ट बांधने के कारण उनका तीन साल का बच्चा रो पड़ा था। भारतीय अधिकारी ने ''नस्ली भेदभाव' का आरोप लगाते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से इस मामले की शिकायत की है। दूसरी घटना अमेरिका के कैलिफोर्निया की है। वहां एक बुजुर्ग सिख को ''नस्ली हिंसा' का निशाना बनाया गया। जांच में पता चला कि हमला करने वाला पुलिस प्रमुख का बेटा है। हालांकि हमलावर के पिता ने बेटे के अपराध पर फेसबुक पर बहुत ही भावुक पोस्ट लिखी है कि ''हमने अपने बच्चों को हिंसा और घृणा नहीं सिखाई, दूसरों के लिए असहिष्णुता हमारी शब्दावली में नहीं है। हमारे मूल्यों के साथ हमें अकेला छोड़ दो।'घृणा-अपराध से जुड़ीं इस तरह की अमानवीय घटनाएं पाकिस्तान, सीरिया, बांग्लादेश जैसे पिछड़े देश में होती तो स्वाभाविक है कि इनका इतना तीखा प्रभाव नहीं होता। लेकिन इंग्लैंड और अमेरिका में इस तरह के घृणा-अपराध की घटनाएं होती हैं, तो जाहिर है कि उनका अर्थ बदल जाता है। इंग्लैंड के समाज ने मनुष्य के गौरव को बहाल करने के लिए लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं। फ्रांस की क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रसार पूरी दुनिया में हुआ। इस तरह आधुनिक उदारवादी मूल्य यदि यूरोप से निकले तो अमेरिका ने उन्हें पोषित किया। यूरोप और अमेरिका ने नस्लवाद के खिलाफ लंबा संघर्ष किया है। वहीं दूसरी ओर,भारत में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्श विचारों के बावजूद अभी भी नस्लवाद और घृणा-अपराध कई रूपों में जीवित हैं। न केवल जीवित है बल्कि हालिया दशकों में इसका तेजी से प्रसार हुआ है। जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर हमारा समाज आज भी एक दूसरे को नफरत से देख रहा है। इन दिनों भारत में कथित गोरक्षकों ने समाज में घृणा अपराध को बढ़ावा दिया है।

भीड़ की हिंसा भी नईशक्ल में सिर उठा रही है। लेकिन आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर भारत इन सारी सामाजिक कुप्रवृत्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। समस्या तब ज्यादा पैदा होती है, जब नस्लवाद के विरुद्ध लड़ाईके प्रतिमान समझे जाने वाले देशों में घृणा-अपराध से जुड़ीं घटनाएं होती हैं। भारत के लिए ये घटनाएं निराश करने वाली हैं।

यह सवाल है कि हम इस तरह की घटनाओं का मुकाबला कैसे करें ? यूरोप के पुनर्जागरण ने जो सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य दुनिया को दिए हैं, भारत ने भी उन्हीं मूल्यों को अपनाया है। जाहिर है कि इंग्लैंड, अमेरिका या किसी अन्य यूरोपीय देशों में भारतीयों के साथ नस्ली भेदभाव किया जाता है, तो हमारे देश में घृणा अपराध के खिलाफजारी लड़ाई कमजोर होती है। इसलिए इंग्लैंड और अमेरिका को इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगानी चाहिए। यदि सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर पर घृणा और नफरत को नियंत्रित नहीं किया गया तो यूरोप और अमेरिका की आधुनिक व्यवस्थाओं की असफलता मानी जाएगी। और इसके दूरगामी परिणाम होंगे जो भारतीय समाज को भी प्रभावित करेगा।

डिजिटल अर्थव्यवस्था के 2022 तक दस खरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमानः प्रसाद

गुवाहाटी।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के 2022 तक 10 खरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है जिससे देश के बेरोजगार युवाओं के लिए 75 लाख से अधिक नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। प्रसाद ने देश में डिजिटल क्रांति में पूर्वोत्तर को एक अहम हिस्सा बताते हुए कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों का जीवन बदलने और जीवन को आसान बनाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने यहां 'डिजिटल विजन डॉक्यूमेंट 2022- नॉर्थ ईस्ट' जारी करने के बाद कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो रही है और भारत की डिजिटल यात्रा के बड़े हिस्से को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट जैसे नए रुझानों से प्रेरित हो रही है। इससे पहले प्रसाद और असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने बोंगरा जिले की टेक सिटी में सामान्य सुविधा केंद्र और स्मार्ट मीटर निर्माण संयंत्र की नींव रखी। माजुली में पूर्वोत्तर बीपीओ प्रमोशन स्कीम के तहत एक बीपीओ केंद्र का उद्घाटन किया गया। डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 जारी करने के दौरान, पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गईं। राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के लिए एक सुरक्षित और सुगम्य वेबसाइट सेवा की वेबसाइट लॉन्च की। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए स्टेट माईजीओवी पोर्टल लॉन्च किए गए।

जन धन खाताधारकों के लिए 15 अगस्त को बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में 32 करोड़ जनधन खाताधारकों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान कर सकते हैं, जो 2019 के संसदीय चुनावों में उनकी पार्टी और सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जनधन खातों में ओवर ड्राफ्ट सुविधा को दोगुना कर 10 हजार रुपए करने की घोषणा कर सकते हैं। फिलहाल इन खातों के 6 महीने ठीक से चलने के बाद 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इसके साथ ही आकर्षक लघु बीमा योजना की भी घोषणा कर सकती है, जिसमें रुपे कार्ड होल्डर्स को मिलने वाले मुफ्त दुर्घटना बीमा की राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का दूसरा चरण 15 अगस्त को पूरा होने जा रहा है। पिछले चार साल में इसके तहत 32.25 करोड़ जनधन खाते खुले, जिनमें में कुल 80,674.82 करोड़ जमा हैं। सूत्रों के मुताबिक, योजना के लिए अब नए लक्ष्य तय किए जाने हैं और इनकी घोषणा के लिए स्वतंत्रता दिवस समारोह सबसे अच्छा अवसर होगा। केंद्र सरकार की वित्तीय समावेशन मुहिम के तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत अगस्त 2014 में हुई थी।

सरकार का वारः 50,000 मुखौटा कम्पनियों की रजिस्ट्रेशन रद्द

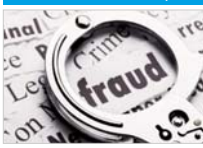

नई दिल्ली।

कालेधन व मनी लांड्रिंग के मामलों को देखते हुए सरकार ने शैल (मुखौटा) कम्पनियों पर एक और वार कर दिया है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एम.सी.ए.) ने पिछले हफ्ते लगभग 50,000 कम्पनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। दिल्ली रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज (आर.ओ.सी.) ने पिछले 3 दिनों में 30,000 से अधिक कम्पनियों पर गाज गिराई और उनकी रजिस्ट्रेशन रद्द की, जबकि मुम्बई आर.ओ.सी. की तरफ से 11,000 से अधिक कम्पनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा देश के अन्य आर.ओ.सी. से भी करीब 9000-10000 मुखौटा कम्पनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द होने की खबरें हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि ये कम्पनियां पिछले 2 सालों से किसी भी तरह का बिजनैस नहीं कर रही थीं और न ही इन कम्पनियों का संचालन हो रहा था। ऐसी कुछ कम्पनियों को अगले कुछ दिनों में आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इन सभी कम्पनियों के रद्द होने की सूचनाएं भेजी गई हैं। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने लगभग 2.5 लाख कम्पनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया था जिन्होंने पिछले 2 साल में लगातार किसी तरह का लेन-देन नहीं किया था यानी जीरो टर्नओवर किया था। 2013 के कम्पनी अधिनियम की धारा 248 के तहत सरकार निष्क्रिय कम्पनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जो लगातार 2 वर्षों तक निष्क्रिय रही हैं। मंत्रालय सीमित देयता साझेदारी (एल.एल.पी.) को कम करने की भी योजना बना रहा है। एम.सी.ए. के अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भी इसी तरह की कम्पनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है।

9 महीने में पहली बार जुलाई में कम हुई यात्री वाहनों की बिक्री, घरेलू बिक्री 2.71 प्रतिशत गिरी

ऑटो डेस्क।

जुलाई महीना इस बार वाहनों कंपनियों के लिए अच्छा नहीं रहा। इस बार वाहन बिक्री के लिए जुलाई महीना स्थिर रहा। अगर यात्री वाहनों की बात करें तो जुलाई में यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री घटी है। पिछले 9 महीनों में ऐसा पहली बार हुआ है। इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि पिछले साल जुलाई में माल एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू किए जाने से वाहनों की बिक्री में आया जबर्दस्त उछाल था। वाहन विनिर्माता कंपनियों के संगठन सियाम के आंकड़ों के अनुसार इस साल जुलाई में यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री 2.71 गिरी है। इस प्रकार कुछ यात्री वाहन बिक्री 2,90,960 इकाई रही। वहीं पिछले माह यह बिक्री 2,99,066 वाहन थी। वहीं घरेलू बाजार में कारों की बिक्री पिछले साल के 1,92,845 इकाई की तुलना में मामूली गिरकर 1,91,979 इकाइ पर आ गई। देश की दिग्गज कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की भी जुलाई में यात्री वाहन बिक्री घटी है। इसका ज्यादा असर तो नहीं दिखा है मामूली तौर पर घटकर 1,52,427 वाहन रही। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जुलाई अवधि में देश में एक करोड़ से अधिक वाहनों का उत्पादन हुआ। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में हुए लगभग 93 लाख वाहनों के उत्पादन के मुकाबले यह 17त अधिक है। आपको बता दें कि इस दौरान व्यावसायिक वाहनों की बिक्री 29.65 प्रतिशत बढ़कर 76,497 इकाई पर पहुंच गई। साथ ही विभिन्न श्रेणियों के सभी वाहनों की बिक्री इस दौरान 7.97 प्रतिशत बढ़ी है। पिछले साल जुलाई के माह में 20,79,204 इकाइ थी।

संक्षिप्त समाचार

रेलयात्रियों को अब मुफ्त में नहीं मिलेगा यात्रा बीमा, रेलवे करेगा योजना में बदलाव

नई दिल्ली। इंडियन रेलवे 1 सितंबर से अपनी बीमा योजना में बदलाव करने जा रहा है। रेलवे अब यात्रियों को मुफ्त यात्रा बीमा का लाभ नहीं देगा। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। रेल मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम ने 1 सितंबर से मुफ्त यात्रा बीमा की सुविधा बंद करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि बीमा का प्रावधान वैकल्पिक होगा। इंडियन रेलवे की कंपनी आईआरसीटीसी के एक अधिकारी के मुताबिक 1 सितंबर से पैसेंजरों से प्रीमियम लेने के साथ ही पैसेंजरों को यह विकल्प भी दिया जाएगा कि वे बीमा सुविधा लेना चाहते हैं या नहीं। वेबसाइट या मोबाइल से टिकट बुक करते वक्त पैसेंजर को दोनों में से एक विकल्प चुनना होगा। यदि पैसेंजर बीमा सुविधा लेना चाहता है तो उसे प्रीमियम की रकम अदा करनी होगी। मालूम हो कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए रोजाना 7 लाख टिकट बुक होते हैं। इनमें से लगभग ढाई से तीन लाख टिकट कन्फर्म होते हैं। यात्रा के दौरान दुर्घटना में यात्री की मौत होती है, तो उसके लिए 10 लाख रुपए तक के बीमे का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से दुर्घटना में अपाहिज होने पर 7.5 लाख और घायल होने पर दो लाख रुपए की रकम का प्रावधान किया गया है।

गोएयर को मिली इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट करने की अनुमति

जालंधर। गोएयर अक्तूबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए फ्लाइट शुरू करेगा। इसके साथ ही विदेश में उड़ान भरने वाली 5वीं भारतीय विमानन कम्पनी बन जाएगी। मौजूदा समय में एयर इंडिया, इंडिगो, जैट एयरवेज और स्पाइसजैट ही इंटरनैशनल फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं। गोएयर को कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दम्मम सऊदी अरब तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही नागर विमानन सचिव आर.एन. चौबे ने कहा कि इंडिगो जहां कन्नूर से दोहा तक उड़ान भरेगी वहीं जैट एयरवेज की उड़ान कन्नूर से अबू धाबी के लिए होगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अक्तूबर के अंत में इसे शुरू कर दिया जाएगा।

अडानी ग्रीन एनर्जी का घाटा पहली तिमाही में बढ़कर हुआ 74 करोड़ रुपए

नई दिल्ली। अडानी ग्रीन एनर्जी का घाटा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बढ़कर 74.26 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी को पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 17 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि आलोच्य तिमाही के दौरान उसकी कुल आय पिछले वित्त वर्ष के 194.13 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 482.42 करोड़ रुपए पर पहुंच गयी। इस दौरान कंपनी का खर्च भी 213.22 करोड़ रुपए से बढ़कर 581.86 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। जून में शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद यह कंपनी का पहला तिमाही परिणाम है। बता दें कि गौतम अडानी की स्वामित्व वाली कंपनी अडानी पावर लिमिटेड ने जून तिमाही में भारी घाटा दर्ज किया है। कंपनी के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा, हमारा मानना है कि भारत जैसे देशों में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना तथा कम लागत में नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र विकसित करना महत्वपूर्ण है। हम 2022 तक 228 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने के सरकार के लक्ष्य के अनुकूल काम कर रहे हैं। हरित ऊर्जा उत्पादन तथा अंतिम छोर तक इसकी पहुंच बढ़ा रहे हैं। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयंत परिमल ने अलग बयान मे कहा, भारत का विद्युत क्षेत्र नवीकरणीय ऊर्जा के साथ तेजी से विकसित हो रहा है और हम इस क्षेत्र में भारी अवसर देख रहे हैं।'' अडानी पावर ने वित्त वर्ष 2019 की पहली तिमाही में 824 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया है। कंपनी ने बीते वर्ष की जून तिमाही में कुल 452 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया था।

इंटरनेट की दुनिया में जल्द ही इन भारतीय भाषाओं में होगा डोमेन नाम

कोलकाता। इंटरनेट डोमेन नाम अबतक आपको अंग्रेजी में ही उपलब्ध थे लेकिन जल्द ही आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी इंटरनेट डोमेन का नाम बना सकेंगे। गैर लाभकारी निगम इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स (आईसीएएनएन) दुनिया भर में इंटरनेट के डोमेन नाम प्रणाली (डीएनएस) का कामकाज देखता है। निगम देश की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं सहित भारत में बोली जाने वाली कई भाषाओं में डोमेन नाम तैयार करने के काम में जुटा है। आईसीएएनएन के भारत प्रमुख समीरन गुप्ता ने ट्रेट' को बताया, भारत की नौ लिपियों बंगाली, देवनागरी, गुजराती, गुरमुखी, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, तमिल और तेलगू पर काम जारी है।

पावर बैंक में हुए ब्लास्ट से जल गई कार, निर्माता कम्पनी और स्नैपडील भरेगी जुर्माना

चंडीगढ़। एंब्रेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित पावर बैंक में अचानक ब्लास्ट हो जाने से एक कार जल गई। जिला उपभोक्ता फोरम ने एंब्रेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ऑनलाइन फर्म स्नैपडील को एक लाख रुपए के हर्जाने सहित कुल 1 लाख 35 हजार 39 रुपए देने का आदेश दिया है। सैक्टर-21 निवासी अंकित महाजन ने स्नैपडील से एक एंब्रेन पी-2000, 20,800 एम.ए.एच. पावर बैंक 1699 रुपए में खरीदा था। खरीदने के 4-5 दिन बाद ही उसमें प्रॉब्लम आ गई। पावर बैंक का एक चार्जिंग पार्ट काम नहीं कर रहा था और वह बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। उन्होंने स्नैपडील से बात की जिन्होंने उसका प्रोडक्ट वापस लेने से इंकार कर दिया। 16 जुलाई, 2016 को वह अपनी कार से ऑफिस जा रहा था। उसने पावर बैंक गाड़ी की पिछली सीट पर रखा हुआ था। वह करीब 2-3 घंटे बाद वापस लौटे तो देखा कि पावर बैंक में ब्लास्ट हो चुका था और कार से धुआं उठ रहा था।

आभूषण विक्रेताओं की लिवाली से बीते सप्ताह सोने में सुधार, चांदी कमजोर

नई दिल्ली।

विदेशों में कमजोर रुख को नजरअंदाज करते हुए त्योहारी सत्र की मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय आभूषण विक्रेताओं की भारी लिवाली के कारण दिल्ली सर्राफा बाजार में बीते सप्ताहांत के अंतिम दौर में सोने की कीमत तेजी के साथ 30,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। हालांकि उतार चढ़ाव भरे कारोबार में चांदी कीमतों में गिरावट आई। बाजार सूत्रों ने सोने की कीमतों में सुधार का कारण घरेलू हाजिर बाजार में त्योहारी सत्र की मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय आभूषण विक्रेताओं की लिवाली बताया लेकिन विदेशों में कमजोर रुख के कारण लाभ कुछ सीमित रहा। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोने की कीमत सप्ताहांत में हानि दर्शाता 1,211.20 डॉलर प्रति औंस जबकि चांदी गिरावट के साथ 15.28 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई। सप्ताह की शुरूआत में छिटपुट लिवाली समर्थन के कारण राष्ट्रीय राजधानी में 99.9 प्रतिशत और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने के भाव में क्रमशः 30,585 रुपए और 30,435 रुपए पर मामूली तेजी रही। बाद में विदेशों में कमजोर रुख के कारण इन्हें कुछ प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और ये कीमतें क्रमशः 30,520 रुपए और 30,370 रुपए तक टूटने के बाद सप्ताहांत में 150-150 रुपए की तेजी के साथ क्रमशः 30,700 रुपए और 30,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुईं। दूसरी ओर सीमित सौदों के बीच उतार चढ़ाव दर्शाने के बाद गिन्नी की कीमत सप्ताहांत में पिछले सप्ताहांत के बंद स्तर 24,600 रुपये प्रति आठ ग्राम पर स्थिर रही।

पेटीएम यूज़ करते है तो इन बातों का रखे ध्यान, एक गलती आपको बना सकती है कंगाल

नई दिल्ली ।

भारत आज तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। देश में पैसों का लेनदेन अधिकतर ऑनलाइन ही हो रहा है। यानि कैशलैस। इसके लिए भीम एप, पेटीएम व कई एप के द्वारा एक दूसरे को घर बैठे पैसे भेजे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हम आप को बता दें कि अगर आप इन एप को इस्तेमाल करते है तो थोड़ा सावधानी भी बरतें. आज अधिकतर लोग पेटीएम यूज कर रहे है, पर आपकी एक भूल आपको कंगाल बना सकती है। हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहे है जिससे आप फाड से बच सकते है। पिछले दिनों पेटीएम पर फर्जी लिंक के द्वारा कई लोगों के साथ ठगी हो चुकी है। एक शख्स ने यूट्यूब से पेटीएम ट्रांजेक्शन का फर्जी लिंक बनाना सीख कर हजारों की ठगी कर ली। इसमें जितनी राशि का भुगतान करना होता है उतनी राशि मैसेज में डालनी होती है। इसी के बाद मैसेज सामने वाले को जब भेजा जाता है तो पता ही नहीं चलता कि मैसेज फर्जी है या असली इसलिए अगर आपको कोई पेमेंट करता है तो पेटीएम के पासबुक में जाकर अपने अमाउंट की जांच कर ले। कभी भी ओटीपी किसी से भी शेयर न करें। जब हम लॉगिन करते हैं तो हमें एक ओटीपी आता है ऐसे में अगर कोई आपके नंबर से अपने फोन में लॉगिन कर आपसे ओटीपी मांगता है तो वह कभी भी न शेयर करें क्योंकि अगर उसने एक बार आपके फोन नंबर का ओटीपी ले लिया तो आपके अकाउंट को एक्सेस कर लेगा। आपको आपके पेटीएम अकाउंट की केवाईसी कम्पलीट करवाने के लिए कहते हैं। इसके बाद वे आपकी डिटेल लेकर ठगी को अंजाम देते हैं इसलिए अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो सबसे पहले इसकी सूचना पेटीएम को दें। पेटीएम ऐप पर बने अकाउंट से आप से किसी भी तरह की धोखाधड़ी होती है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऐप के सबसे ऊपर वाले कोने पर बने प्रोफाइल आइकन पर क्लॉक करना है। जैसे ही आप इस आइकन पर क्लॉक करेंगे, तो आपके सामने 24×7 का एक विकल्प दिख जाएगा। आपको इस पर क्लॉक करना है। क्लॉक करने के बाद आपके सामने एक लंबी लिस्ट खुलेगी। इस लिस्ट में थोड़ा नीचे जाकर आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाला विकल्प चुनना है।

यहां पर क्लॉक करते ही आपके सामने कुछ नये विकल्प खुलेंगे। आपके साथ जिस तरह की धोखाधड़ी हुई है, उसके हीं साथ से विकल्प चुनें। अब जो आपके सामने विंडो खुलेगी। उस पर आपको घटना का पूरा ब्यौरा देना है।

टॉप 10 कंपनियों में से 7 कंपनियों का मार्केट कैप 47,499 करोड़ रुपए बढ़ा

नई दिल्ली। देश की टॉप 10 में से 7 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) बीते सप्ताह 47,498.74 करोड़ रुपए बढ़ा। इनमें सबसे ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज रही। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, एचडीएफसी, इंफोसिस और भारतीय स्टेट बैंक के बाजार पूंजीकरण में वृद्धि दर्ज की गई। जबकि मारुति, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और कोटक महिंद्रा बैंक का बाजार पूंजीकरण इस अवधि में घटा है। रिलायंस का बाजार पूंजीकरण 17,270.09 करोड़ रुपए बढ़कर 7,63,053.04 करोड़ रुपए हो गया। इसी प्रकार एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण 12,597.94 करोड़ रुपए बढ़कर 5,73,232.15 करोड़ रुपए हो गया। इस दौरान, टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 6,317.15 करोड़ रुपए बढ़कर 7,63,360.46 करोड़ रुपए रहा। एसबीआई का बाजार पूंजीकरण 5,220.89 करोड़ रुपए बढ़कर 2,71,709.07 करोड़ रुपए हो गया। इंफोसिस के बाजार पूंजीकरण में 4,608.51 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ और यह 3,02,545.31 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसी प्रकार आईटीसी का बाजार पूंजीकरण 1,306.69 करोड़ रुपए बढ़कर 3,72,459.79 करोड़ रुपए और एचडीएफसी का बाजार पूंजीकरण 177.47 करोड़ रुपए बढ़कर 3,33,892.33 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ, कोटक महिंद्रा का बाजार पूंजीकरण इस दौरान 4,270.16 करोड़ रुपए घटकर 2,45,305.58 करोड़ रुपए रहा जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाजार पूंजीकरण में 2,326.98 करोड़ रुपए की कमी आयी और यह 3,78,529.51 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। मारुति के बाजार पूंजीकरण में इस दौरान 1,117.69 करोड़ रुपए की कमी देखी गई और यह 2,76,444.04 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

अब देश में सी-प्लेन उड़ाने का सपना होगा पूरा, मोदी सरकार ने दी हरी झंडी

नेशनल डेस्क।

अब देश में भी सी प्लेन चलाने का सपना पूरा होने जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में सी-प्लेन उतारने के लिए अड्डे बनाने की मंजूरी दे दी है। इसके पहले चरण के लिए ओडिशा के चिल्का झील और गुजरात के सरदार सरोवर बांध तथा साबरमती रिवर फ्रंट की पहचान की गयी है। एक अधिकारी ने आज इसकी जानकारी दी। इस प्रस्ताव को नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने मंजूरी दी। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इस संबंध में इस साल जून में नियमन जारी किया था जिसमें जलाशयों में बने एयरोड्रम के लाइसेंस की जरूरतों एवं प्रक्रियाओं का जिक्र किया गया था। अधिकारी ने कहा कि चूंकि किसी भी विमानन कंपनी से इस क्षेत्र में बाजार व मांग संबंधी ऐतिहासिक आंकड़े नहीं मिले हैं, परियोजना पर प्रायोगिक तौर पर काम किया जाएगा। इससे हवाई संपर्क को विस्तृत करने के लिए एम्फीबियन विमानों (जल एवं स्थल दोनों से उड़ान भरने में सक्षम) के परिचालन का रास्ता तैयार होगा। प्रस्ताव के तहत पर्यटन तथा धार्मिक महत्व के स्थानों के नजदीक ऐसे एयरोड्रम बनाये जाएंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने इसके लिए ओडिशा, गुजरात, असम, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में जगहों की पहचान पहले ही कर ली है। अधिकारी ने कहा कि पहले चरण में जलाशयों में एयरोड्रम बनाने के लिए ओडिशा में चिल्का झील तथा गुजरात में सरदार सरोवर बांध और साबरमती रिवर फ्रंट की पहचान की गयी है। इससे पहले नागर विमानन सचिव आर.एन.चौबे ने भी कहा था कि उनका मंत्रालय उड़ान योजना के तीसरे चरण के तहत सीप्लेन का परिचालन शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। डीजीसीए के अनुसार, जलाशय में बने एयरोड्रम के लिए आवेदन करने वाले किसी भी निकाय को रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और नौवहन मंत्रालय समेत विभिन्न प्राधिकरणों की मंजूरी लेनी होगी।

सचीन नोटीफाई क्षेत्र में तालाव में डूबने से एक बच्चे की मोत, अवैध रूप से बनाया तलाब

डायमंड इंडस्ट्रीज और डायमंड पार्क के अधिकारियों की आपा धापी में बच्चा बना शिकार

डूबने वाला लडका

सचीन। डायमंड के पास तालाब में आगम नवकार सोसाइटी में रहता 14 साल का लड़का डूबने से हुये मोत. जिसके चलते आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो जाने से अग्निशामक दल को जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर खोजबीन करने से मृत शरीर लगभग २.०० बजे मिला.

घटना सचीन नोटीफाई क्षेत्र सुरत सुर-सेज में डायमंड इंडस्ट्रीज में कुछ दिनों पहले से नई मिलों-कारखाने का जमीन बांधकाम के लिए नई विस्तारित किया गया था .उसमें जमीन को समतल करने के लिए और अन्य जगहों पर जमीन से माटी के अवैध रूप से निकाल कर एक तालाब बना दिया गया. जिसमें बारिस के पानी भरने से यह तालाब में पूरा पानी भरा जाने के बाद तालाब से कुछ ही दुरी पर आये पार्क पब्लिक स्कुल के बच्चे रविवार का दिन होने से खेलते हुये इस तालाब में नहाने लगे. जिसमें तीन दोस्त में से एक शशांक नामक बच्चे का तालाब में डूबने से मोत हो गया .

स्थानिक लोगों का कहना हैं की यह तालाब अवैध रूप से बनाया गया हैं जिसमें किसी भी प्रकार की मंजूरी या जमीन से माटी निकालने का रोयल्टी भी नही भरा गया हैं. प्लोटहोल्डर और जमीन मालिक अपने निजी फायदे के लिए ३५ थी ४० फुट गहरा और ५० से ६० फुट के गड्ड खोद कर इसे मोत का घर बना दिया.

जिसमें सुबह १० बजे के आसपास में पार्क पब्लिक स्कुल में पड़ाई कर रहे तीन दो घूमते हुये इस तालाब में नहाने के लिए उतरे जिसमें से तालाब ज्यादा गहरा होने से शशांक नामक बच्चे डूब जाने से मोत हुये. एक माता पिता ने अपना बेटा खो दिया है। एक माता पिता ने अपना बेटा खो दिया है। इस अबैध तालाब से संबंधित आधिकारी और विभाग क्या कानूनी कार्यवाही किया जाएगा ?. डायमंड इंडस्ट्रीज और डायमंड पार्क के अधिकारी अपने जेब भरने के लिए इस तरह के अनेक अवैध काम कर रहे हैं क्या ?

सुडा के अधिकारियों की नाक के निचे अवैध निर्माण की भरमार

सूरत। सूत्रों के पास मिली जानकारी से सुरत शहेरी विकास के विस्तार में लगता हैं की पूर्ण रूप से ओफ़िसर,अधिकारी सिर्फ सुडा भवन से ही सारे काम पूर्ण करते हैं.किसी फरियाद या आवेदनकर्ता को फरियाद करने पर उसे ही हेरान ? परेशान करने का मामला सामने आया हैं, जिसमें फरियादकर्ता को ही आरोपी बना देते हैं,कि किसी भी प्रकार की फरियाद दुबारा न कर सके .फरियाद करने पर अधिकारीगण अपना -अपना हिस्सेदारी की रकम ले कर कोई कार्यवाही नही करते हैं.सुडा विस्तार के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी जगहों पर अवैध रूप से कार्य हो रहे हैं, जिसकी जानकारी होने के बाद भी यह विभाग किसी प्रकार की कार्यवाही न करके अपने पद का फ़ायदा उडाते हैं, एक बिल्डर ने यह भी कहा की कोई भी फरियाद करने पर इस तरह से सेटिंग्स होते हैं कि अधिकारी कोई भी कार्यवाही नही करते हैं, एक बिल्डिंग बनाने में लगभग कुछ(५०,०००) पचास हजार रकम खर्च करना पड़ा हैं. क्या सच्चाई हैं ? इन आधिकारियों के पीछे. क्या इस बात की जानकारी अन्य अधिकारी को होने के बावजूद कोई कार्यवाही नही हो रही हैं. ? कई बिल्डिग बनाने के कुछ दिनों में ही भय जनक हालत में होने के बावजूद कोई कार्यवाही नही होती. क्यों ? नगरपालिका,तलाटी, की मिलिभगत से चल रहा सारे अवैध जमीन का कारोबार क्या सही हैं ?. क्या इसमें कोई बड़े व्यकित का हाथ हैं राजकीय ?

राज्यभर के शिवालय ओम नमः शिवाय के नारे से गूंजे

सोमनाथ महादेव, नागेश्वर महादेव सहित के तीर्थधाम में शिवभक्त पहुंचेंगे : आज सावन महीने का पहला सोमवार

अहमदाबाद । रविवार से पवित्र सावन महीने का प्रारंभ होने की वजह से अहमदाबाद शहर सहित राज्यभर के शिवालय हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के पवित्र नारे से गूंज उठे । सुबह से ही महादेव के दर्शन दूध-जलाभिषेक, बेलपत्र का अभिषेक, चावल, काला तल सहित के अभिषेक करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु भक्तों में हौड़ मच गई थी सोमनाथ महादेव, नागेश्वर महादेव सहित के ऐतिहासिक तीर्थधाम में तो सावन महीने के पहले दिन ही भक्त भारी संख्या में पहुंचते है । सौराष्ट्र का सोमनाथ महादेव तो सावन महीने को लेकर बहुत ही आकर्षक और दिव्यता के साथ सजाया गया है । इस बार सोमनाथ महादेव मंदिर को दो हजार से ज्यादा एलईडी लाइट से जगमगाएगा । जिसे लेकर मंदिर की शोभा में अद्भूत वृद्धि हुई है । सावन महीने को लेकर सभी शिवमंदिरों में भोलानाथ के विशेष श्रृंगार और पूजा-अर्चना और आरती -प्रसाद का आयोजन किया गया है । अहमदाबाद शहर में भी सावन महीना रविवार से शुरू होने के साथ ही शिवभक्तों में उपवास, तप, आराधना और भक्ति का माहौल छाया रहा है । इस वर्ष में सावन महीना की शुरूआत और खत्म दोनों रविवार के दिन होता है । इस वर्ष में पवित्र सावन महीने में चार सोमवार आएगा । सावन के सोमवार को शिवभक्ति का बहुत शास्त्रोक्त और अनोखा महात्म्य रहा है । सावन महीने की शुरूआत अहमदाबाद के प्रसिद्ध रखियाल के चकुडीया महादेव, रायपुर चकला के चकुडीया महादेव, थलतेज के कैलास टेकरी, सारंगपुर के प्राचीन कर्णमुक्तेश्वर महादेव, बोडकदेव के पारदेश्वर महादेव, गांधीनगर के प्रसिद्ध धोलेश्वर महादेव सहित के शिवालय में श्रद्धालु भक्त काफी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे । अहमदाबाद शहर सहित राज्यभर के शिवालय हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, के पवित्र नारे से गूंज उठे । सौराष्ट्र के प्रसिद्ध सोमनाथ महादेव, द्वारका के पास नागेश्वर महादेव सहित के शिव मंदिरों में पूजा-अर्चना, महाआरती, शिवपुराण, दूध-जल, धन-अनाज का अभिषेक करके शिवभक्ति के माहौल में व्यस्त हो गये ।

राजकोट के फायरमैन के चौंकाने वाला खुलासा

मूंगफली गोदाम जल जाने के लिए उप कलेक्टर पर दबाव था

मूंगफली गोदाम १०१ फीसदी आधा बचाया जा सकता लेकिन उप कलेक्टर ने काम करने से मना कर दिया

अहमदाबाद । राज्यभर में जल रहे मूंगफली के गोदाम के मामले में चौंकाने वाले खुलासे करते हुए राजकोट के फायरमैन की ऑडियोक्लीप वायरल होने पर गुजरात की राजनीति में खलबली मच गई है । विपक्ष पार्टी के नेता के साथ यह फायरमैन की बातचीत की ऑडियोक्लीप में फायरमैन सनसनी खुलासा कर रहा है कि हमने गोंडलवाली मूंगफली गोदाम १०१ फीसदी आधा बचाया जा सकता लेकिन उप कलेक्टर ने काम करने से मना करने पर यह आग में जलने दिया । फायरमैन के इस खुलासे बाद अब मूंगफली घोटाला और इसके विभिन्न गोदाम में लगी आग के प्रकरण में बड़ी मछली और सरकार के उच्च अधिकारियों के विरूद्ध आशंका है ।

राजकोट के एक फायरफाइटर के फायरमैन और विपक्षी नेता परेश धानाणी के बीच बातचीत में सभी मूंगफली घोटाले का खुलासे हो रहे है । फायरमैन बताते है कि, हमने आग छिड़काव करते समय मूंगफली बोरी के बीच से कई डीजल के केन मिले थे और गोंडल का आधा गोदाम जल जाने से बचाया जा सकता था लेकिन उप कलेक्टर ने काम करने से मना कर दिया जलने दिया । राज्य सरकार ने किसानों के पास से मूंगफली समर्थन मूल्य पर खरीदी भी सरकारी गोदामों यह बचा नहीं सके । गोंडल, पेढला, राजकोट यह कई जगहों पर एक के बाद एक मूंगफली गोदाम जल गया । करोड़ों की मूंगफली जल गई और कई केस भी हुए । यह रहस्य अभी कायम रहा है क्योंकि किसने जलाया अब फायरमैन के चौंकानेवाला खुलासा नये गंभीर प्रश्न सामने आ रहे है कि यदि मूंगफली गोदाम जल जाने से बचाया जा सकता था तो गोदाम जलकर खाक हो जान में किसे रूचि था और किसकी सूचना के आधार पर सरकारी अधिकारियों ने आग बुझाने के कामकाज को रोका था, गोदाम में लगी आग के पीछे किसका हाथ था और सबसे बड़ी बात यह इसके पीछे का इरादा और कौन-सी राजनीति थी यह गंभीर सवाल उठाये गये है ।

हार्दिक ने मंजूरी मांगी तो, एएमसी ने मैदान पार्किंग प्लोट घोषित किया

अहमदाबाद । पास के कन्वीनर और पाटीदार युवा नेता हार्दिक पटेल का अनिश्चितकालीन उपवास आंदोलन २५ अगस्त से शुरू हो रहा है तब हार्दिक पटेल की तरफ से एएमसी प्रशासन के पास शहर के विभिन्न क्षेत्र में स्थित बड़े तीन मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मंजूरी मांगी गई है यह मैदानों को अब एएमसी प्रशासन पार्किंग प्लोट के तौर पर घोषित कर दिया है, जिसे लेकर अब पूरे मामले में एक नया मोड़ आया है । दूसरी तरफ पाटीदार आरक्षण आंदोलन को एएमसी प्रशासन के इस रवैये को बेबुनियाद बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश बतायी जा रही है । एएमसी प्रशासन द्वारा शहर के निकोल क्षेत्र में शुकन चार रास्ते के पास तथा सरोवर प्लाजा के सामने मैदान सहित के पांच से ज्यादा मैदान अचानक ही पार्किंग प्लोट के तौर पर घोषित किया गया है ।

राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई

एमआर. शाह ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लिया

अहमदाबाद । गुजरात हाईकोर्ट के वरिष्ठ और जज एमआर. शाह ने रविवार को बिहार के पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लिया । पटना के राजभवन के दरबार होल में रविवार को सुबह में ११ बजे खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी, कानूनमंत्री नरेन्द्र नारण यादव सहित के महानुभावों की उपस्थिति में आयोजित हुए भव्य शपथविधि समारोह में गुजरातभर में लोकप्रियता प्राप्त करनेवाले गुजरात के न्यायतंत्र के गौरवसमान ऐसे वरिष्ठ न्यायाधीश एमआर. शाह को राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी गई । इस अवसर पर जस्टिस एमआर. शाह के परिवारजनों, मित्रों, पटना हाईकोर्ट तथा गुजरात हाईकोर्ट और न्यायतंत्र के पदाधिकारियों सहित के महानुभाव विशेष रूप से उपस्थित हुए । आज के शपथविधि समारोह की सबसे उल्लेखनीय बात है कि, रविवार से महादेव के पवित्र सावन महीने की शुरूआत हुई है तब आज के दिन एमआर. शाह ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लिया है और सोमवार को सावन महीने का पहला सोमवार है यह पवित्र दिन में सोमवार से एमआर. शाह पटना हाईकोर्ट के नये चीफ जस्टिस के तौर पर अपना पद संभाल लेंगे । पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर शपथ लेने के बाद सिर्फ गुजरात और बिहार ही नहीं लेकिन देशभर के न्यायतंत्र में से ईमानदार जस्टिस को शुभकामना और अभिनंदन के संदेश प्राप्त हुए । उल्लेखनीय है कि, अहमदाबाद शहर में आवारा पशुओं की समस्या हो या खराब रास्तों की बात ,सादिक जमाल एन्काउन्टर केस हो या फिर लोगों के स्वास्थ्य और प्राथमिक सुविधाओं की बात हो कई मामलों को लेकर गुजरात हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश एमआर. शाह ने कई महत्वपूर्ण फैसले देकर पूरे न्यायतंत्र में एक श्रेष्ठ उदाहरण दिया है और न्यायतंत्र में एक सुनहरा इतिहास रचा है ।

भारत के उपराष्ट्रपति नायडू अधेलाइ से नारी के बीच फॉर ट्रेक रोड के शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित हुए । इसके पहले हवाईअड्डे पर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया । राज्यपाल कोहली, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जीतुभाई वाघाणी और मंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा उपस्थित हुए ।

महादेव मीडिया
रोहताश यादव 9924144499, 7015339195
बीजिटिंग कार्ड, बिल बुक, लेटर पैड, बेनर, पोस्टर, आदि का डिजाइन बनवाने के लिए संपर्क करें। (हिन्दी, गुजराती)
हिन्दी, गुजराती न्युज पेपर डिजाईन करवाने के लिए संपर्क करें।
304 केवल कॉम्पलेक्ष नवा गाम, डिंडोली, उधना सूरत।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com